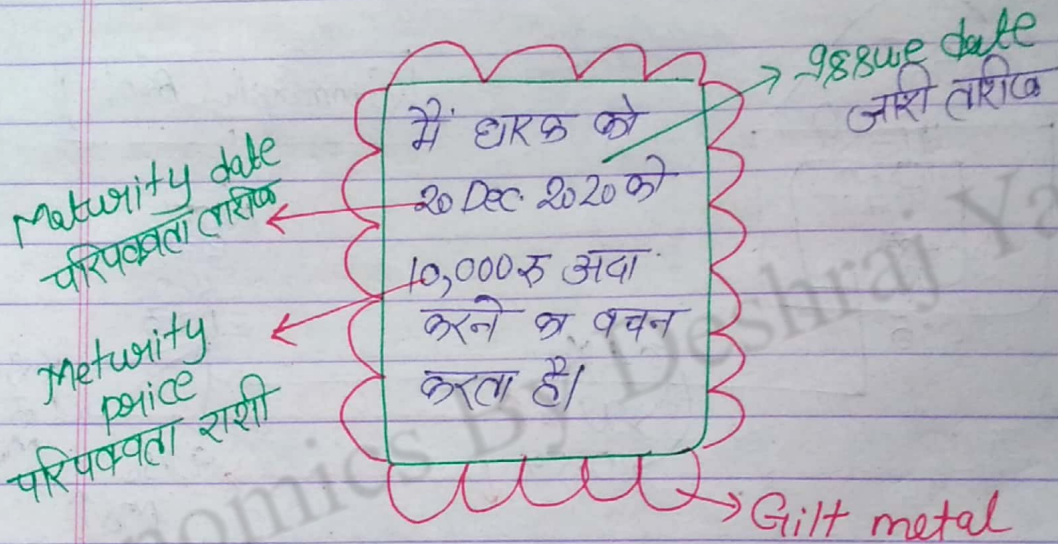


IV

SLR → बैंकों के पास जमा कुछ धनराशि का वह प्रतिशत जो बैंकों के स्वयं अपने पास रखना चाहता है और यह राशि नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखी जा सकती है।

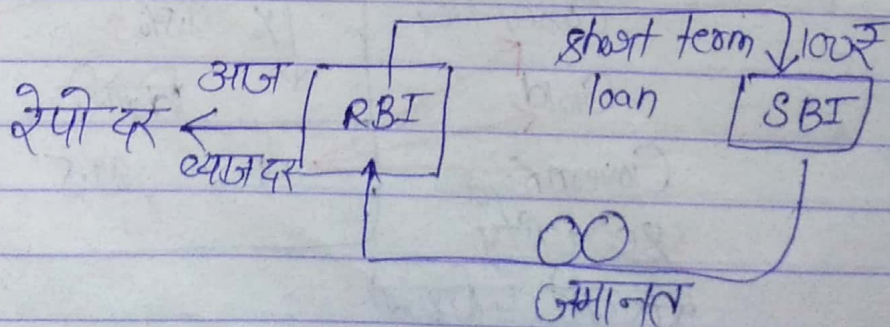


Notes - सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलाने वाला व्याज सामान्य व्याज से कम होता है।

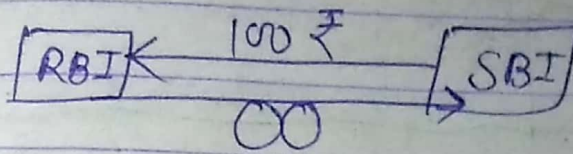
Repo Rate:



Repo charge + obligation



का



रेपो दर वह दर होता है जिस दर पर RBI दूसरे वाणिज्यिक बैंकों को अल्पवधि ऋण प्रदान करता है और इसके साथ वाणिज्यिक बैंक यह वादा भी करते हैं कि वह ऋण के लिए रखी ~~सुध~~ ^{जमानत} को खरीद लेंगे।

Reverse repo rate:-

RRR वह दर है जिस दर पर RBI दूसरे वाणिज्यिक बैंकों से अल्पवधि ऋण लेता है। और इसी के साथ यह वादा भी करता है कि वह जमानत को वापस खरीद लेगा।

Open Sell Market:-

खुला बाजार परिसंचन RBI द्वारा जब खुले बाजार में सरकारी अनुभूतियों का क्रय या विक्रय किया जाता है तो इसे खुला बाजार परिसंचन कहते हैं।

Asset (सम्पत्ति) हमारी
Liability (परिसम्पत्ति) किसी दूसरे की

Budget / बजट

Revenue Budget

राजस्व

recurring in nature

दोहरती हुई

→ Not affecting any asset or Liability
ना सम्पत्ति ना देयता का प्रभाव

Capital Budget

पूंजीगत

⇒ सम्पत्ति अथवा देयता का प्रभाव करते हैं।

⇒ loan, Borrowing, Repayment
Road, schools, dam.

Revenue Budget
राजस्व

Revenue receipt

राजस्व आय

→ Receipts

eg:- Tax (कर), "Profit of PSU"
(सरकारी कंपनी से लाभ)
Penalties, Registration of fees

1.7 trillion Dollar
India

America → His spend defence

1st Largest exp. of Govt
भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च

Revenue Expenditure

राजस्व व्यय

→ Int. payment

व्यय भुगतान

→ Salary तनखा

Defence Expenditure

सुरक्षा खर्च

→ maintenance (रखरखाव)

Capital Budget पूंजीगत बजट

Capital receipts

पूंजीगत आय

Assets ↓ Liability ↑

eg. → Borrowing

⇒ Disinvestment
विनिवेश

Capital expenditure

पूंजीगत व्यय

Asset ↑ Liability ↓

100 → 50
Initial Remain

eg. making (Metro, schools)

, Road, dam,

(Repayment of loan)

obj. → For his development.

“ विकास ”

Tax/कर

→ Compulsory Payment

(निश्चित भुगतान)

obj. → निश्चित कार्य के उद्देश्य

के लिए

Cess/उपकर

eg. - Swachh Bharat Cess } Public
Kishhi Kalyan Cess } Account

Madhyamika Siksha cess

obj. → Tax on Tax

उपकर

Surcharge/अधिभार

eg. 100 रु

10

10

+ 1

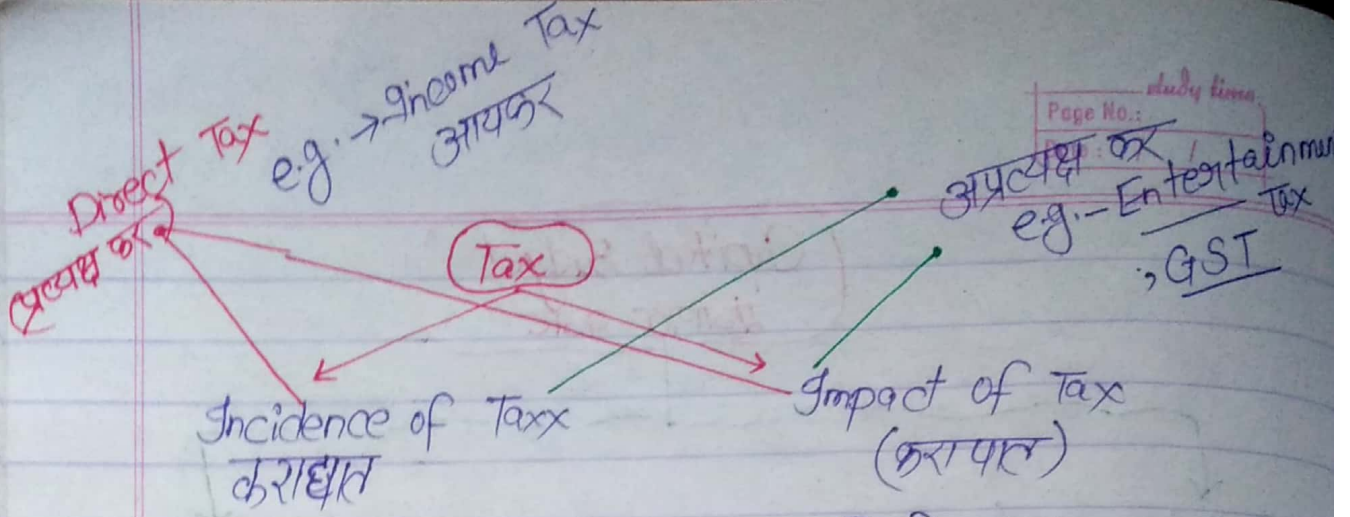
121 रु

~~Tax 10%~~

Tax 10%

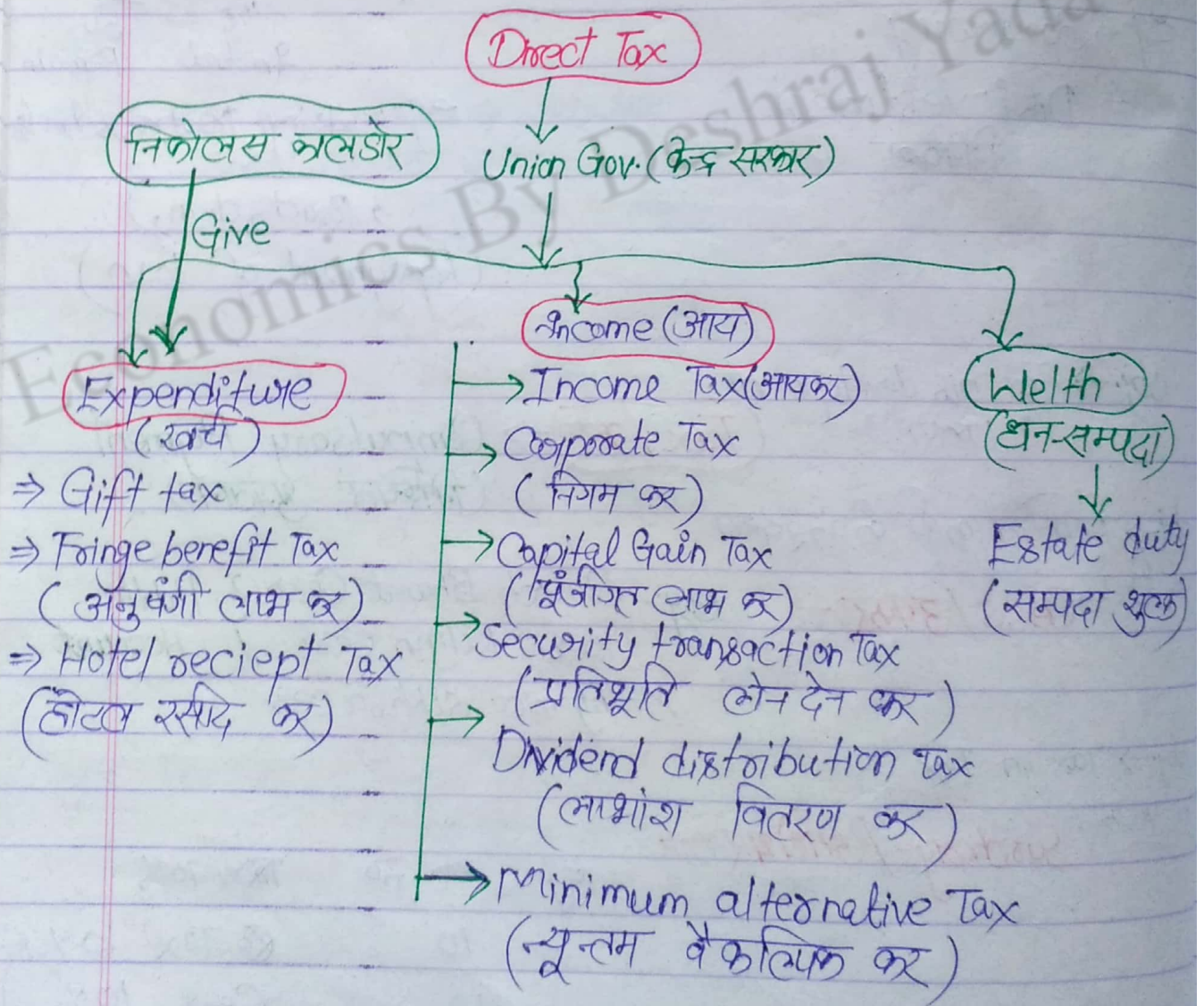
Cess 10%

Surcharge 10%



⇒ जिसपर कर लगाया जाये।
On whom Tax is imposed.

⇒ जिसके द्वारा कर चुकाया जाये।
By whom tax paid.



अनुबंधी लाभ कर → अनुबंधी लाभ कर केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाने वाला वह प्रत्यक्ष कर है जो कर अनुबंधी लाभ पर

आरोपित किया जाता है अनुवर्गी लाभ वेतन के अतिरिक्त कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले लाभों को कहते हैं।

जैसे → फ्री आवास (Accommodation)
फ्री यातायात (Transportation)

हेल्थ रसीद कर :- → प्रत्यक्ष कर होता है।

Estate duty / सम्पदा शुल्क :-

यह केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। पूर्वजों के द्वारा स्थानान्तरित सम्पत्ति पर केन्द्र सरकार द्वारा जो प्रत्यक्ष कर आरोपित किया जाता है उसे सम्पदा-शुल्क कहते हैं।

10/01/2020

Direct Tax

Income

Income Tax

James Wilson

Father of I.T. in India

Corporate Tax → Corporate of Company
(निगम कर)

→ भारत सरकार की सबसे बड़ी आय का ह्रास

Net profit → Income Expe

Net profit = सकल लाभ
- depreciation ह्रास
= Net profit

नियम कर केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाने वाला वह प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों की विसुद्ध लाभ पर किया जाता है और यह भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है।

Capital Gain Tax / पूंजी लाभ कर :-

पूंजी लाभ कर, प्रत्यक्ष कर है जो C.O.I के केन्द्र सरकार से लगाया जाता है। पूंजी को बेचने पर जो लाभ होता है उसे पूंजी लाभ कहते हैं और इस लाभ पर केन्द्र सरकार जो प्रत्यक्ष कर आरोपित करती है उसे पूंजी लाभ कर कहते हैं।

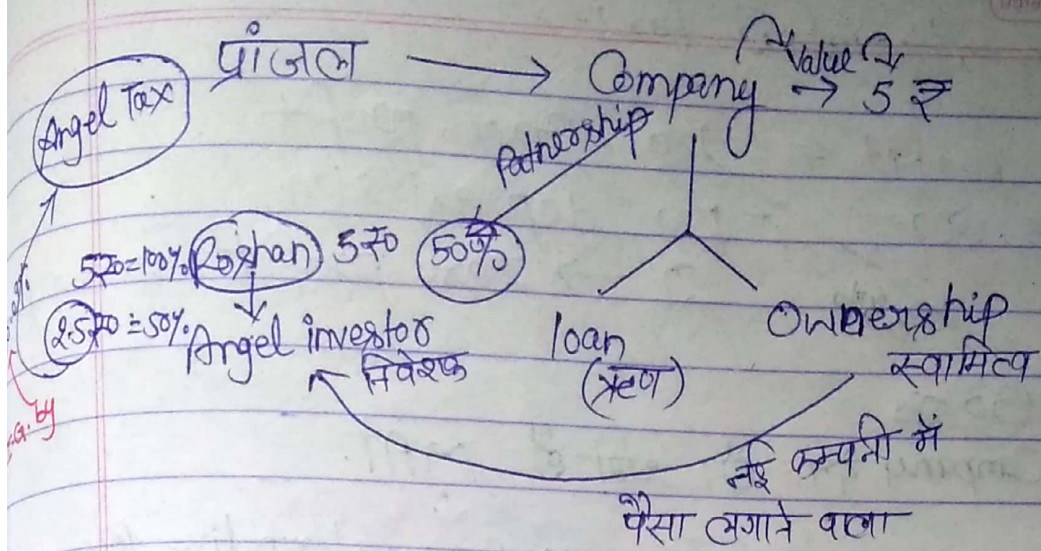
पार्षद सारकी सोम समिति का सम्बन्ध कर सुधारों से है एवं उसमें भी इसका सम्बन्ध पूंजी लाभ कर से है।

पार्षद सारकी सोम समिति ने बार नियम दिये

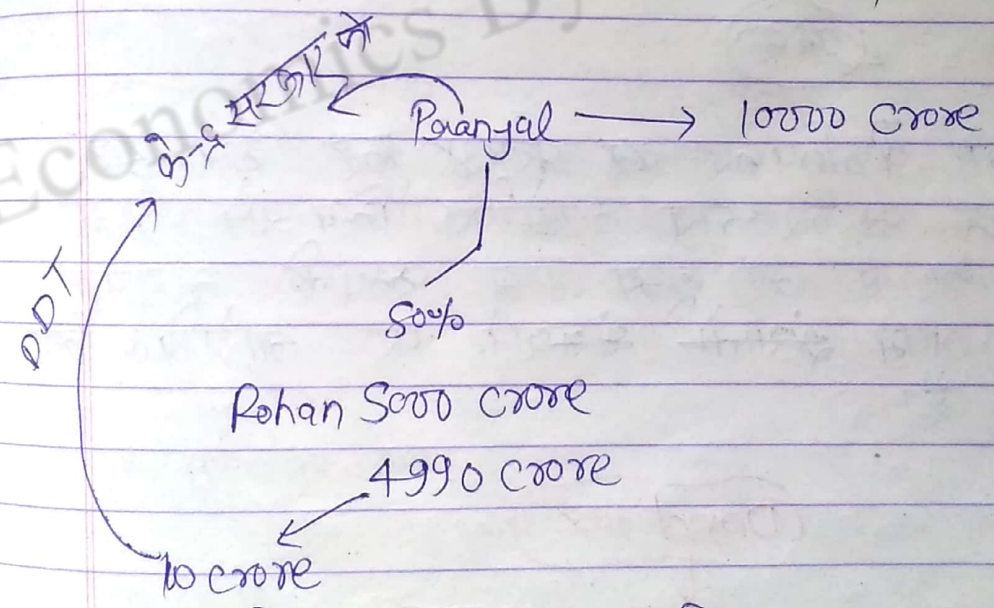
राजा जे. चेलैया समिति यह आयकर से सम्बन्धित समिति है।

Security Transaction Tax / प्रतिभूति लेन देन कर :-

प्रतिभूतियों के लेन देन पर केन्द्र सरकार द्वारा जो प्रत्यक्ष कर आरोपित किया जाता है उसे प्रतिभूति लेन देन कर कहते हैं।



एंगल टैक्स → एंगल टैक्स आयकर का वह प्रकार होता है जो एंगल निवेशक द्वारा कंपनी का अधिमूल्यन कर लगाये गये पैसे पर आरोपित किया जाता है।



कंपनी द्वारा लाभों का वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा जो कर आरोपित किया जाता है उसे लाभों का वितरण कर कहते हैं।
~~dividend~~ dividend distribution Tax

Minimum alternative tax:-

$$\begin{array}{rcl} \text{Net profit} & = & 100 \text{ Gross profit} \\ \text{निरव लाभ} & - & 100 \text{ depreciation} \\ \hline & = & 0 \rightarrow \text{Zero profit company} \end{array}$$

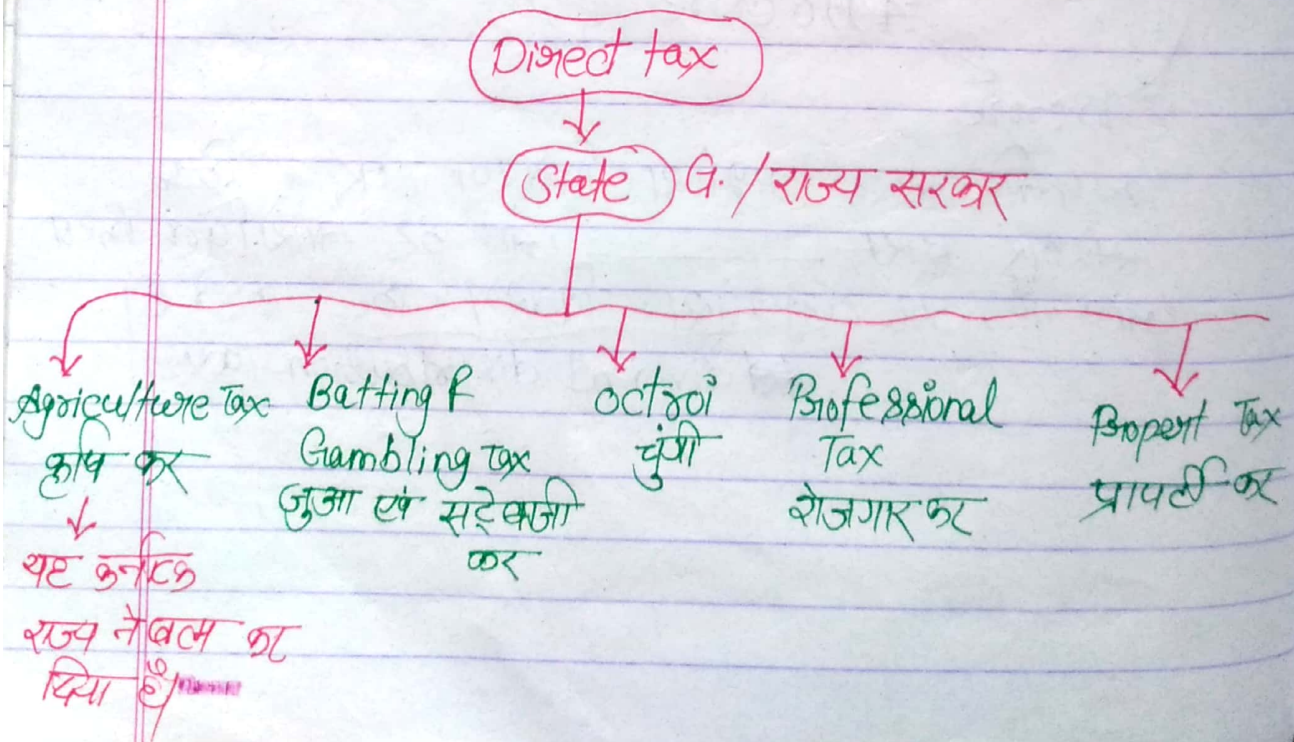
← 33%

(33%) रु
Company देना है। यही है MAT.

↓
Minimum alternative tax.

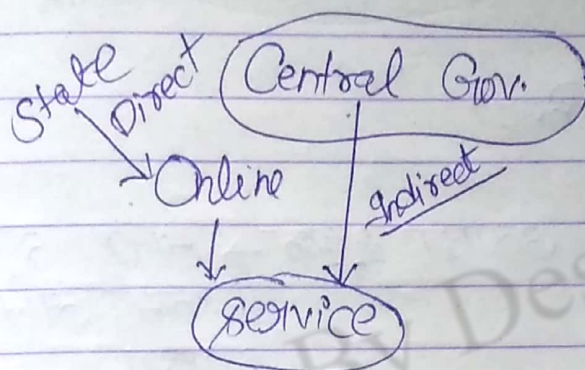
$$\begin{array}{r} 100 \\ - 10 \\ \hline 90 \\ \hline \text{(24 रु)} \end{array}$$

न्यूनतम वैकल्पिक रूप से प्रत्यक्ष कर है। इसे केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाने वाला वह कर है जो शून्य लाभ कंपनी अथवा गैर लाभ संस्थानों संस्थानों पर आरोपित किया जाता है।



कृषि पर राज्य सरकार द्वारा आरेपित किया जाने वाला वह प्रत्यक्ष कर है जो कृषि भूमि पर न्यूनतम दर से आरेपित किया जाता है।

G. & G. Tax:-



Octroi:- जुंगी कर एक प्रकार का प्रवेश कर होता है यह राज्य सरकार द्वारा आरेपित किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। यह महाराष्ट्र को छोड़कर सम्पूर्ण राज्यों से समाप्त कर दिया है।

Professional Tax:-

Property Tax:-

इसे शहरी निकाय लगाते हैं।
Urban Government

प्रापर्टी कर शहरी क्षेत्रों में प्रापर्टी खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा एक न्यूनतम कर लगाया जाता है। इसे प्रापर्टी कर कहते हैं।

Indirect Tax/अप्रत्यक्ष कर

↓ Union (केन्द्र)

उत्पादन
शुल्क

सीमा
शुल्क

सेवा
शुल्क

विक्री कर

मूल्यवर्धन
कर

वस्तु एवं
सेवा कर
(G.S.T.)

सभी वस्तु → केन्द्र

राज्य सरकार :- उत्पादन शुल्क → मानव उपभोग में काम आने वाली मदिरा
→ नार्केटिक्स एवं ड्रग्स

Excise duty/उत्पादन शुल्क :-

केन्द्र सरकार सभी वस्तुओं के उत्पादन पर जो अप्रत्यक्ष कर आरोपित किया जाता है, उत्पादन शुल्क कहते हैं।

लेकिन मानव उपभोग में आने वाली मदिरा, नार्केटिक्स एवं ड्रग्स पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकार आरोपित करती है।

वसा कर, कैरब सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह जंक खाद्यों पर आरोपित किया जाता है।

सीमा शुल्क/Custon duty:-

वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर केन्द्र सरकार जो कर लगाती है, उसे सीमा शुल्क कहते हैं।

Anti dumping duty/अतिरिक्त सीमा शुल्क :-

वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर केन्द्र सरकार द्वारा

द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, अतिरिक्त सीमा शुल्क कहते हैं।

Dumping

भारतीय मार्किट = 10 ₹
चीन मार्किट = 5 ₹

When dumping duty एक प्रकार का सीमा शुल्क है। यहाँ उन आपरित वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा दिया जाता है जिनकी कीमत घरेलू वस्तुओं की कीमत से कम होती है।

Mirror Tax:- भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के कर लगाये जाने के कारण Mirror Tax चर्चा में रहा।

Service Tax/ सेवा शुल्क:-

Sales Tax/ बिक्री कर:-

Farmer - गेहूँ → 10 ₹ → 1
Flour mill - आटा → 20 ₹ → 2
Baker - Bread → 30 ₹ → 3
Wholesaler - " " → 40 ₹ → 4
Retailer - " " → 50 ₹ → 5

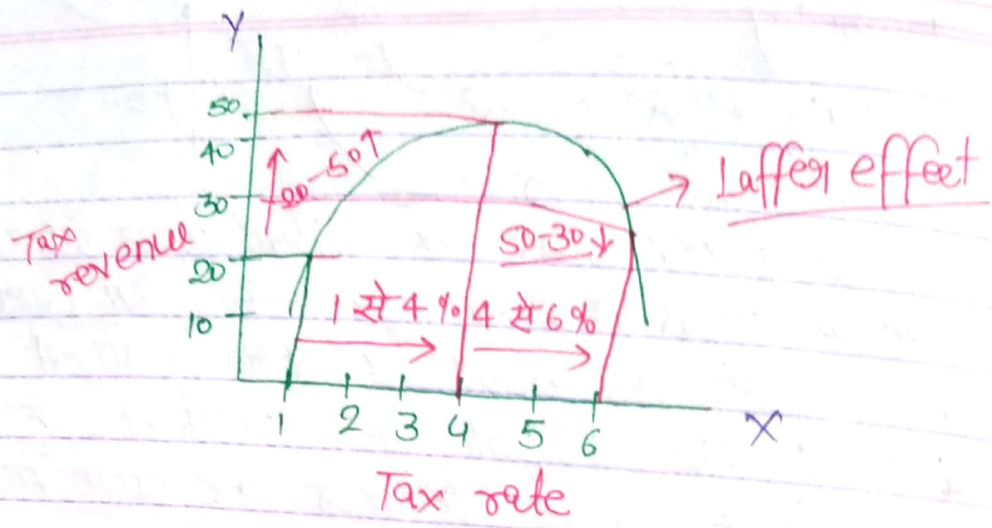
10% Sales Tax

50 + 15 = 65 ₹

→ Cascading effect of Tax
कर का हार्पांकित प्रभाव

Laffer = Tax rate ↑ ⇒ Tax revenue ↑
राजस्व में बढ़ो

Tax rate ↑ ⇒ Tax revenue ↓



कर का दायित्व प्रभाव :-

बार-बार करारोपण किया जाय तो उसे कर का दायित्व प्रभाव कहते हैं। और कर का दायित्व प्रभाव कर के दर में वृद्धि कर देने पर कर राजस्व में भी वृद्धि होती है, कर राजस्व में कमो हो जाती है।

Angle's Law :- Bad money drives out good money from economy
 काला धन श्रेष्ठ धन को उद्योगस्था से बाहर कर देता है।

14/01/2020

L.K. Jha Committee :→ 19 जुलाई 1969

Germany ⇒ France

Value addition Tax

Haryana become 18th state लागू करने वाला।

→ संशोधित मूल्यवर्धन कर

Modified value addition Tax

MODVAT

वर्ष 2002 → विजय केलकर समिति

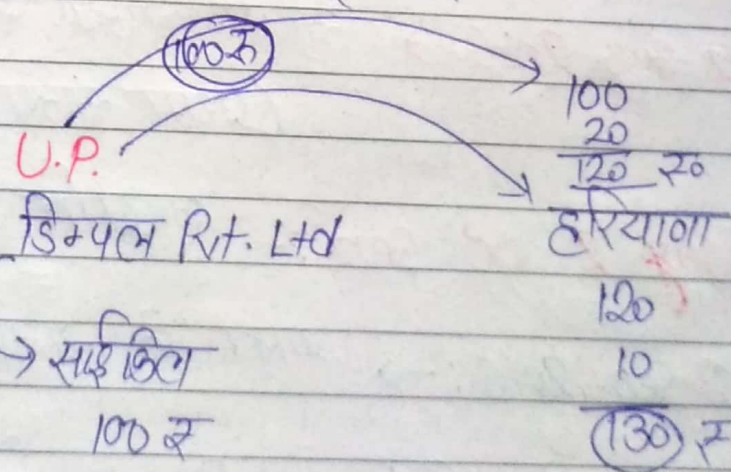
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर में सुधार

2003 :- (i) Integrated Tax (एकीकृत कर)

(ii) Destination based Tax मंजिल आधारित कर

फ्रांस: GST
↓
वस्तु व सेवा कर

eg.



डिम्पल R.T. L+V

→ सप्लाइंग

100 रु
10 रु
110
+10 रु
120

100
20
120 रु
हरियाणा
120
10
130 रु

Kattar R.T. L+V
Cycle → 100 रु
10
10
130 रु

वर्ष 2009 :- असीम दास गुप्ता समिति ।

:- GSTIN GST सूचना तंत्र विकसित

⇒ 2011 :- 115वाँ संशोधन विधेयक

× (खर्च हो गया लोक सभा भंग होने की वजह से)

2014 :- 19 Dec. 2014

122nd C.A. Bill

लोकसभा में पेश
(Presented in lok sabha)

2016 :- 3 Aug. → 2016 → राज्यसभा में पास

यही विधेयक पुनः 8 Aug 2016 :- लोकसभा में पास

12 Aug. 2016 → असम राज्य ने पास कर दिया।
(प्रथम राज्य)

~~08 Aug~~ 2 08 Sep. :- राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये।

16 Sep. 2016 :- भारत के राजपत्र में प्रकाशित।

⇒ 101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

→ G.S.T. लागू करने वाला 1st state → तेलंगाना।

1 July 2017 से G.S.T. सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया।